

## Details of the Cases of Power Theft

**\*42 Ch. MAMMAN KHAN (Ferozpur Jhirka):**

Will the Energy Minister be pleased to state:-

- a) the constituency wise number / details of the cases of power theft caught by the Government in district Nuh from 1st April, 2019 till to date;
- b) the copy of LL-1 checking report alongwith calculation sheet of every theft case mentioned above;
- c) whether the above mentioned LL-1 checking reports and calculation sheets have been made according to the Government sale circular no. D-21/2017 and D-43/2017; if not, the action taken by the Government against the delinquent/erring officials/officers;
- d) the amount collected from the abovesaid theft cases in rural areas and urban areas of district Nuh separately; and
- e) whether the Government will refund the collected amount, which has been incorrectly calculated in the abovesaid LL-1 checking reports and calculation sheets; if so, the time by which the said amount is likely to be refunded; if not, the reasons therefor?

**RANJIT SINGH, ENERGY MINISTER**

Sir,

- a) No. of theft cases caught during the period from 1<sup>st</sup> April, 2019 to 31<sup>st</sup> July, 2023 in Nuh, Punhana, Firozpur Zhirka, Hathin and Sohna constituencies of Nuh District are 2799, 3535, 4182, 23 (being partial area in Nuh district) and 2177 respectively.
- b) The information sought is too voluminous and comes to about 20,000 pages. No useful purpose will be served by giving this voluminous data.
- c) As a matter of rule, calculation sheets are prepared as per Sales Circular No. D-21/2017. However, as per provision of Sales Circular No. D-43/2017, any consumer aggrieved upon the decision of assessing authority may file appeal before appellate authority.
- d) Amounts of Rs. 895.59 Lacs and Rs. 413.24 Lacs have been collected from the rural and urban areas respectively of Nuh District.
- e) Wherever, discrepancies are found in calculation sheet, amount will be refunded. Secondly similar action will be taken after examination of representation if any received in this regard from affected consumer / person. The exercise will be completed within six months.

## बिजली चोरी के मामलों का ब्यौरा

### \*42 चौ. मामन खान (फिरोजपुर झिरका):

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

- (क) जिला नूंह में 1 अप्रैल, 2019 से आज तक सरकार द्वारा पकड़े गए बिजली चोरी के मामलों की निर्वाचनक्षेत्र वार संख्या /ब्यौरा क्या है;
- (ख) एल.एल.-1 जांच रिपोर्ट की प्रति तथा ऊपर वर्णित प्रत्येक चोरी के मामले का परिकलन पत्र उपलब्ध कराया जाए;
- (ग) क्या ऊपर वर्णित एल.एल.-1 जांच रिपोर्टों तथा परिकलन पत्रों को सरकार विक्रय/ बिक्री परिपत्र संख्या डी-21/2017 तथा डी-43/2017 के अनुसार बनाया गया है; यदि नहीं, तो सरकार द्वारा दोषी/गलती करने वाले कर्मचारियों /अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;
- (घ) जिला नूंह के ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों से उपरोक्त चोरी के मामलों में पृथक-पृथक कितनी राशि एकत्रित की गई है; तथा
- (ङ) क्या सरकार एकत्रित राशि को वापिस करेगी जिसकी गलत गणना उपरोक्त एल.एल.-1 जांच रिपोर्टों तथा परिकलन पत्रों में की गई है; यदि हां, तो उक्त राशि के कब तक वापस किए जाने की संभावना है; यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

### रणजीत सिंह, ऊर्जा मंत्री

श्रीमान जी,

- क) जिला नूंह के नूंह, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, हथीन और सोहना निर्वाचन क्षेत्रों में 1 अप्रैल, 2019 से 31 जुलाई, 2023 तक पकड़े गए चोरी के मामलों की संख्या क्रमशः 2799, 3535, 4182, 23 (जिला नूंह में आंशिक क्षेत्र होने के कारण) और 2177 है।
- ख) मांगी गई जानकारी बहुत विस्तृत है और लगभग 20 हजार पृष्ठों की है। इतना विस्तृत डाटा देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
- ग) नियमानुसार, गणना शीट सेल्ज परिपत्र संख्या डी-21/2017 के अनुसार तैयार की जाती हैं। हालांकि, सेल्ज परिपत्र संख्या डी-43/2017 के प्रावधान के अनुसार, आकलन प्राधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी उपभोक्ता अपीलकर्ता प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
- घ) जिला नूंह के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र से क्रमशः 895.59 लाख रुपये और 413.24 लाख रुपये की राशि एकत्र की गई है।
- ङ) जहां भी गणना शीट में विसंगतियां पाई जाएंगी, तो राशि वापिस कर दी जाएगी। इसके अलावा यदि प्रभावित उपभोक्ता/व्यक्ति से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है, तो जांच के बाद इसी तरह के कार्रवाई की जाएगी। यह कार्य छह महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।